1	2	3	4	5
किनू/माल्टा	पंजाब	10,000	दिसम्बर 1992 से	"ए" श्रेणी 3.25 रु० प्रति
	हरियाणा	2,000	फरवरी 93 के	किलोग्राम "बी" श्रेणी
	उत्तर प्रदेश	2,000	दौरान खरीदे	2.75 रु०
	राजस्थान	500	जाने वाले	प्रतिकिलोग्राम "सी" श्रेणी 2.25 रु० प्रति कि० ग्रा०

पेड़ों पर छिड़के जाने वाला तेल और कीटनाशी

3822. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेड़ों पर छिड़के जाने वाले तेल और कीटनाशकों तथा जीवनाशकों के बढ़ते हुए मूल्य के कारण इन्हें खरीदना मुश्किल ही नहीं, बल्कि असंम्भव हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो किसानों और बागान मालिकों को राहत देने की दृष्टि से सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) तथा (ख) कीटनाशियों तथा कृमि-नाशियों के औसत मूल्यों में कोई असामान्य वृद्धि देखने में नहीं आई है। तथापि 1992 के दौरान ट्री सेड आयल के मूल्य लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़े। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को, कीटनाशियों पर सबसिडी उपलब्ध है।

Registration of Firms under Insecticides Act

3823. SHRI G.Y. KRISHNAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that NEEM based Insecticides are more effective to protect foodgrains and Crops from Insects and pests, are environmental friendly and now world recognise its effectiveness and having outstanding scope of raw-materials in the country, but Central Insecticide Board, Registration Committee and other concerned authorities and departments are not giving proper attention for its publicity, if so, what are the details thereof;

(b) what are Insecticides, Fungicides, Herbisides Technical and their formulations which are being granted registration under section 9(4) of the Insecticides Act, 1968;

(c) what are the names of the parties/ firms with their addresses who have been granted registration under section 9(3B) of the Insecticides Act with date and validity;

(d) the names of the parties, their addresses with products and quantity, who have been allowed Import by the Registration Committee on provisional registrants under the Insecticides Act during the last two years and criteria for allowing of such Import and on whose recommendations, party-wise and product-wise; and

(e) the names of the parties and products whose provisional registrations are pending with the Registration Committee and since when and the quantum of Import requested and criteria for considering such Import requests?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Neem based insecticides have been reported to be effective against number of stored grains and some crop pests. Since Neem based insecticides are environmental friendly, these are considered an important possible input for Integrated Pest Management and the Registration Committee has allowed its

commercialisation though these are only provisionally registered.

Use of Neem based insecticide is also promoted through Extension media.

A 'Neem Newsletter' is being published by Indian Agricultural Research Institute on quarterly basis for dissemination of information on various aspects of Neem based Insecticides.

(b) Details are given in *Annexure-(See* Appendix CLXV, Annexure No. 67.)

(c) Details are given in *Annexure-(See* Appendix CLXV, Annexure No. 68.)

(d) Provisional registrations are granted to the new molecules introduced for the first time in the country for generating data only under Indian ., agro-climatic conditions. Registration Committee allowed sufficient quantity of pesticide to be imported for conducting trails on 1000 acres in each crop. Other details are given in *Annexure-III. '(See* Appendix CLXV, Annexure No. 69)

(e) Details of the firms and the products whose applications are pending with the Registration Committee for grant of 'provisional registration as on 30.11.92 are given in *Annexure-IV. (See* Appendix CLXV, Annexure No. 70)

Criteria for import of a pesticide as mentioned in reply to part (d) of the Question is applicable here also.

केन्द्रीय मरुभूमि अनुसंधान संस्थान

3824. श्री राम नरेश यादव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन केन्द्रीय मरु भूमि अनुसंधान संस्थान के पाली केन्द्र में हुए करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति के घोटाले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो घोटाले में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि इस घोटाले की जांच के लिए परिषद द्वारा नियुक्त अधिकारी के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ङ) क्या यह सच है कि उक्त घोटाले का पर्दाफाश करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों को संस्थान के उच्च अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका): (क) महोदय, इस संबंध में शिकायतें मिली हैं।

(ख) पहले विभागीय जांच के आदेश दिए गए परन्तु इसके बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच के लिए इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सुपुर्द कर दिया गया।

(ङ) जी नहीं।

Allocation of Fertilisers to States

3825. SHRI G.Y. KRISHNAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the details of allocation of fertilizers to individual States and Union Territories along with the names of the companies authorised to supply;